पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

लखनऊ विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार कर सम्पूर्ण लखनऊ जनपद को दायरे में लाने की आवश्यकता : मुख्यमंत्री

बाराबंकी विकास प्राधिकरण के गठन का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश

प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों की सीमाओं का भी आवश्यकतानुसार विस्तार करने के लिए ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं

लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेस–वे कॉरिडोर के नियोजित विकास को उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण में शामिल करते हुए तेजी से आगे बढ़ाया जाए

उ0प्र0 राज्य राजधानी क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित क्षेत्रीय योजना–2051 के प्रारूप को निर्धारित समय–सीमा में अन्तिम रूप दिया जाए

लखनऊ में अर्बन रेजिलिएंस, रायबरेली में विनिर्माण एवं डिफेंस इंजीनियरिंग, उन्नाव में औद्योगिक विस्तार, बाराबंकी में कृषि–उद्योग एवं ईको–टूरिज्म, हरदोई में सण्डीला औद्योगिक कॉरिडोर और सीतापुर में नैमिषारण्य के अनुरूप पर्यटन विकास को केन्द्र में रखकर क्षेत्रीय नियोजन किया जाए

प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से पूर्ण की जाए, प्रत्येक विकास प्राधिकरण में स्थायी टाउन प्लानर की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए

गाजियाबाद में अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

लखनऊ : 24 नवम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि लखनऊ के सुनियोजित एवं समग्र विकास के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा का विस्तार कर सम्पूर्ण लखनऊ जनपद को इसके दायरे में लाने की आवश्यकता है। उन्होंने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी आज यहाँ अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाराबंकी में नए विकास प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए भी विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों की सीमाओं का भी आवश्यकतानुसार विस्तार करने के लिए ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रस्तावित सीमा विस्तार पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ जनपद की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती आबादी की आवासीय, व्यावसायिक और सामुदायिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही, राजधानी के बाहरी क्षेत्रों में अवैध एवं अनियंत्रित निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एल0डी0ए0 का विस्तार आवश्यक है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि वर्ष 1974 में गठित एल0डी0ए0 का वर्ष 1999, वर्ष 2009 और वर्ष 2014 में विस्तार किया गया था। वर्तमान में इसके अधिकार क्षेत्र में नगर महापालिका क्षेत्र और 306 राजस्व ग्राम शामिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 1,051 वर्ग किलोमीटर है।

मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से सटे बाराबंकी में भी तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार, औद्योगिक गतिविधियों और आवासीय दबाव को देखते हुए नए विकास प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजधानी के निकट होने के कारण बाराबंकी में भूमि उपयोग और निर्माण गतिविधियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में आवश्यक है कि विकास को शुरुआत से ही सुनियोजित दिशा दी जाए, ताकि भविष्य में बुनियादी ढाँचे, जल निकासी और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएँ न पैदा हों। उन्होंने बाराबंकी विकास प्राधिकरण के गठन का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेस–वे कॉरिडोर के विकास की समीक्षा करते हुए कहा कि कॉरिडोर उन्मुख विकास की कार्यवाही को उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण में शामिल करते हुए तेजी से आगे बढ़ाया जाए। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस कॉरिडोर का एकीकृत नियोजन करते हुए आर्थिक विकास की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाया जाए।

अधिकारियों ने अवगत कराया कि यूपीसीडा की सीमा और लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेस–वे के तीन किलोमीटर दक्षिण के बीच लगभग 470 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 171 गाँव और अचलगंज नगर पंचायत शामिल हैं। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र का निर्मित दायरा दोगुने से अधिक हो चुका है। वर्ष 2015 में यह 1,962 हेक्टेयर (4.19 प्रतिशत) था, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 2,656 हेक्टेयर (5.67 प्रतिशत) और वर्ष 2025 में 3,902 हेक्टेयर (8.33 प्रतिशत) हो गया।

मुख्यमंत्री जी ने गाजियाबाद में अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में 35 से 40 हजार दर्शकों की क्षमता वाला अन्तरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन आपसी समन्वय से रेवेन्यू शेयर मॉडल पर निर्माण की सम्भावनाओं का अध्ययन करें और विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें।

बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित क्षेत्रीय योजना–2051 की प्रगति और प्रस्तावित परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि योजना के तहत सर्वेक्षण, बेस मैप तैयार करने और क्षेत्रीय विकास की परिकल्पना से जुड़े प्रारम्भिक चरण पूरे कर लिए गए हैं। अब आमजन की आपत्तियों और सुझावों के लिए क्षेत्रीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसे 30 नवम्बर, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित समय–सीमा में प्रारूप योजना को अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए। आमजन से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए। अन्तिम स्वीकृति के बाद अगले पाँच वर्षों की अल्पकालीन परियोजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए।

राज्य राजधानी क्षेत्र की भौगोलिक एवं आर्थिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों ने अवगत कराया कि लखनऊ (जनसंख्या 45,89,838), सीतापुर (44,74,446), हरदोई (40,92,845), बाराबंकी (32,60,699), उन्नाव (31,08,367) और रायबरेली (29,03,507) को मिलाकर यह क्षेत्र 27,826 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी वर्तमान आबादी 2.92 करोड़ है, जिसके वर्ष 2051 तक बढ़कर 4.9 करोड़ होने का अनुमान है। इस अवधि में शहरीकरण का स्तर भी 29 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तक पहुँचने की सम्भावना है। वर्ष 2025 में 3.58 लाख करोड़ रुपये की नॉमिनल जी0डी0पी0 और 6.7 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर के साथ यह क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 12 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने राज्य राजधानी क्षेत्र की विकास योजना तैयार करते समय प्रत्येक जनपद की विशिष्ट क्षमताओं और आर्थिक सम्भावनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। लखनऊ में अर्बन रेजिलिएंस, रायबरेली में विनिर्माण एवं डिफेंस इंजीनियरिंग, उन्नाव में औद्योगिक विस्तार, बाराबंकी में कृषि–उद्योग एवं ईको–टूरिज्म, हरदोई में सण्डीला औद्योगिक कॉरिडोर और सीतापुर में नैमिषारण्य के अनुरूप पर्यटन विकास को केन्द्र में रखकर क्षेत्रीय नियोजन किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने विकास प्राधिकरणों की कैडर संरचना और मानव संसाधन की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण शहरी नियोजन के लिए पर्याप्त एवं योग्य मानव संसाधन आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से पूर्ण की जाए। साथ ही, शहरी नियोजन के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक विकास प्राधिकरण में स्थायी टाउन प्लानर की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

————————